

## मध्यप्रदेश शासन

### वन विभाग

कमॉक/एफ-5/21/2002/10/3

भोपाल, दिनांक

अप्रैल 2003

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:— वन विभाग में प्रशमन हेतु लंबित वन अपराध प्रकरणों को निरस्त करने संबंधी ।


---

राज्य शासन वन विभाग में प्रशमन हेतु लंबित वन अपराध प्रकरणों को निरस्त करने के संबंध में एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि :—

- (1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिनांक 30-6-2002 के पूर्व पंजीबद्ध समस्त वन अपराध प्रकरण जिनका अभियोजन न्यायालय में प्रारंभ नहीं किया गया है, समाप्त करने की कार्यवाही की जाए । इन प्रकरणों में वाहन की जप्ती एवं राजसात से संबंधित प्रकरण, अतिक्रमण एवं वन्य प्राणी से संबंधित प्रकरण एवं संरक्षित क्षेत्रों में पंजीबद्ध प्रकरण शामिल नहीं होंगे । परन्तु वर्ष 1980 के पूर्व के वनभूमि के अपात्र अतिक्रमकों में से उन अतिक्रमकों के प्रकरण भी इनमें शामिल होंगे, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत शासन को भेजे गए पात्रता के मापदण्डों के अन्दर पात्र पाए जाते हैं । इन प्रकरणों में लंबित वसूली रोक दी जाए एवं ऐसी वनोपज जो वन अपराधियों के कब्जे में है, उसको उन्हीं के पास रहने दिया जाए ।
- (2) 30 जून, 2002 के बाद पंजीबद्ध समस्त प्रकरण भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार निराकृत किये जाए । यदि समयावधि में अपराधी द्वारा अपराध का प्रशमन संपूर्ण नहीं कराया जाता है तो प्रकरण अनिवार्यतः सक्षम न्यायालय में अभियोजन हेतु प्रस्तुत किया जाए ।
- (3) वन अपराधों के अभियोजन का कार्य संपादित करने हेतु प्रत्येक वन मण्डल में एक सहायक वन संरक्षक की पदस्थी की जाए । परन्तु इसके लिये सहायक वन संरक्षक संवर्ग में कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाए ।

- (4) अपराधों के अभियोजन पर होने वाले व्यय हेतु एक अलग बजट मद निमित्त किया जाए जिसमें वन विभाग में गैर योजनामद में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाए ।
- (5) वन अपराधों के अभियोजन के लिए विभिन्न जिलों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के पेनल में से अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाए एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अधिवक्ताओं को विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा पेनल के लिये निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाय । अपराधियों के परिवहन, भोजन इत्यादि पुलिस विभाग के लिये स्वीकृत दरों के अनुरूप वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(रतन पुरवार)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2003.

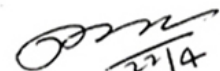
पृ0क0/एफ-5/21/2002/10/3

प्रतिलिपि :-

1- प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य वन विकास निगम,भोपाल ।

2- मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

केतु अग्रेषित ।

  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग